HRA En USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (il) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] No. 677] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2000/आश्विन 28, 1922

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2000/ASVINA 28, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

आदेश

मई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2000

का.आ. 948(अ). — केन्द्रीय सरकार ने, भारत में वर्तमान में उपयोग में लाए जाने वाले कतिपय नाशक जीवमारों की समीक्षा करने और उनके आगे निरन्तर उपयोग के बारे में या अन्यथा विचार करने के लिए एक विशेषक्ष समृष्ट का गठन किया था;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रिजस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसीए) का आयात, विनिर्माण, निर्माण, विक्रय, वितरण और उपयोग मनुष्यों, जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए परिसकटमय है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप आदेश बनाने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

प्रारूप आदेश

केन्द्रीय सरकार की यह राय है, कि एल्डीकार्ब, क्लोरबेमजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसीए) का आयात, विनिर्माण, निर्माण, विक्रय, वितरण और उपयोग मनुष्यों, जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए परिसंकटमय है, अत: यह प्रस्ताय करती है कि उक्त नाशक जीवमारों के आयात, विनिर्माण, निर्माण पर इस आदेश के राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से पूर्णत: पाबन्दी लगा दी जाएगी और उनका उपयोग उनके उपयोग की अवधि की समाप्ति की तारीख से या इस आदेश के राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिषिद्ध हो जाएगा।

एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलङ्किन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इंडीबी), मेलिक हाइङ्गाजाइड और ट्रिक्लोरी एसिटिक एसिड (टीसीए) के आयात, विनिर्माण, निर्माण के लिए नए रजिस्ट्रीकरण या विनिर्माण अनुज्ञप्ति पर पाबन्दी होगी।

एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलब्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसीए) का आयात, विनिर्माण या निर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने वाले विभिन्न व्यक्तियों को विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां उन फर्मों या व्यक्तियों की बाबत रद्द कर दी जाएंगी।

2851 GI/2000

ऐसे रिजस्ट्रीकरण कराने वालों की बाबत जिन्होंने अभी तक विनिर्माण अनुक्रित प्राप्त नहीं की है, एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलिड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइब्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसीए) की बाबत रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रस्ताव है।

्रें इस आदेश की तारीख से पूर्व विनिर्मित स्टाक का उपयोग उक्त उत्पाद के खुद के जीवन काल किन्तु दो वर्ष से अधिक की अवधि तक अनुक्षत बना रहेगा उसके पश्चात् उसका उपयोग प्रतिषिद्ध हो जाएगा।

राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त होंगी जिन्हें वे इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझें।

प्रारूप आदेश जिसे सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की जिसमें यह आदेश अन्तर्विष्ट है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

यदि उक्त प्रारूप आदेश की बाबत कोई व्यक्ति कोई सुझाव या आक्षेप करना चाहता है तो वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए संयुक्त सचिव (पौध सरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवम, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा।

> [फा. सं. 17-2/98-पीपी 1] पी. ही. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture and Co-operation) ORDER

New Delhi, the 20th October, 2000

S.O. 948(E).—Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) is satisfied that the import, manufacture, formulation, sale, distribution and use of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) involves health hazards to human beings, animals and environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following draft Order, namely:-

Draft Order

Whereas the Central Government is of the opinion that the import, manufacture, formulation, sale, distribution and use of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) involves health hazards to human beings, animals and environment and therefore, proposes that the import, manufacture, formulation of the said pesticides shall be banned completely from the date of the final publication of this Order in the Official Gazette and their use shall be prohibited from the date of their expiry or the period of two years from the date of final publication of this Order in the Official Gazette, whichever is earlier.

There shall be a ban on new registration or manufacturing license for import, manufacture or formulation of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA).

The manufacturing licenses issued to various registrants for import, manufacture or formulation of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) for setting up of manufacturing units shall be cancelled in respect of those firms or persons.

It is proposed to cancel the Certificate of Registration in respect of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing licenses.

The use of stock manufactured before the date of this Order shall continue to be permitted till the period of shelf-life of the product, but not exceeding two years after which the use shall be prohibited.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

[F. No. 17-2/98-PP. 1] P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.